कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष:64 अंक:8 मुम्बई जुलाई 2020

आयोग ने नीरा ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए अनूठी परियोजना शुरू की

हनी मिशन से जुड़ने के लिए युवा शिक्षित लोग मधुमक्खी पालन की गतिविधियाँ को अपना रहे हैं

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष:64 अंक:8 मुम्बई जुलाई 2020

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
दिलीप पालकर
सुबोध कुमार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056 के लिए ई-प्रकाशित

ईमेलः kvicpub@gmail.com
वेबसाइटः www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में

समाचार सार .... 3 से 14

कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के बाद "हनी मिशन" कार्यक्रम ने गति पकड़ी............

डा. संघमित्रा कुमरे, आयोग की मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त...............

पाक फायरिंग के बीच, जम्मू-कश्मीर में केवीआईसी हनी मिशन का विस्तार..............

केवीआईसी के नीरा एवं ताड़गुड़ उद्योग में प्रवेश से नए रोजगार व जैविक उत्पादों के सामने आने की संभावना...

आयोग ने पोखरण की कुम्हारी प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया..........................

परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण के उद्देश्य से आयोग ने नई पहल के रूप में चंदन एवं बांस के वृक्षारोपण की शुरुआत की..

आयोग ने वाराणसी के कुम्हार समुदाय के 80 परिवारों को सशक्त बनाया, परिवार "स्वदेशी ओनली" के नए ध्वजवाहक...

सीएपीएफ कैंटीन में राष्ट्रीय ध्वज, खादी कुर्ता और जैकेट केवीआईसी की पहली 'स्वदेशी' आपूर्ति..

प्रेस कवरेज:सोशल मीडिया एवं ई-पेपर ....15 से 16

कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के बाद "हनी मिशन" कार्यक्रम ने गति पकड़ी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के बाद "हनी मिशन" कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है। 1 जून को लॉकडाउन अवधि के तुरंत बाद अरुणाचल प्रदेश के चुल्लियु गांव में 250 मधुमक्खी के बक्से के वितरण के साथ कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ।

इस साल फरवरी में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान चुल्लियु गाँव में एक मधुमक्खी-पालनगृह (अप्रीयर) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश के उन क्षेत्रों को और सशक्त बना रहा है जो अब तक अछूते और अप्रयुक्त बने हुए हैं। हालांकि, देशव्यापी लॉकडाउन के बाद काम ठप हो गया था।

आयोग ने 25 ग्रामीणों को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए, जिन्होंने केवीआईसी को आजीविका के स्रोत के रूप में गांव में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। राज्य में वनस्पतियों की प्रचुरता के साथ, अरुणाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाले शहद के केंद्र बनने की क्षमता है, जिसमें समृद्ध औषधीय मूल्य हैं और इसलिए, उन्हें प्रीमियम मूल्य पर बेचा जा सकता है।

डा. संघमित्रा कुमरे, आईआरपीएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त

डा. (सुश्री) संघमित्रा कुमरे, आईआरपीएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. संघमित्रा ने 23 जून, 2020 को आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। वे आईआरपीएस 2002 बैच (भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा) की सिविल सेवक हैं। डॉ. संघमित्रा योग्य मेडिकल डॉक्टर (एमबीबीएस) हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए एम.एस. ऑबस्टेट्रीक्स एंड गॉयनेकॉलजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) से इस्तीफा दे दिया था।

वह पश्चिम रेलवे में एचआर एंड वेलफेयर की प्रमुख रही हैं, जिसमें लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं। उन्हें रेलवे में उनके कार्य के लिए जरनल मैनेजर्स एवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह पश्चिम रेलवे की कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने में सहायक रही हैं। वह पश्चिमी रेलवे के सांस्कृतिक और ललित कला संघ की सचिव भी थीं और उन्हें इस क्षेत्र में कई प्रशंसा मिली। वे कार्यक्रमों के संचालन में कौशल रखती हैं, और कई आधिकारिक कार्यक्रमों की मेजबानी करती रही हैं।

डॉ. संघमित्रा आईएनएसईएडी, सिंगापुर, आईसीएलआईएफ, मलेशिया और जियोटॉंग विश्वविद्यालय, चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अग्रिम प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं। वह बहुमुखी व्यक्तित्व वाली प्रशासक हैं।

प्लास्टिक से मुक्त गांव चुलिलु, सबसे अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों का निवास स्थान है। गाँव में आदिवासी आबादी ज्यादातर खादी पहनती है और खाने के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल करती है और पीने के लिए कप और गिलास बांस से बनाती है। चूँकि गाँव में प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए यह स्थान शहद का काम करने और उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने के लिए अनुकूल प्रदूषण रहित वातावरण प्रदान करता है।

चुल्लियु गांव में उच्च गुणवत्ता वाली जैविक सब्जी और फलों की फसलें पैदा होती हैं, जैसे दालें, तिलहन, शकरकंद, मटर, अनानास, आड़ू, आलूबुखारा, बादाम, लीची, पपीता और अखरोट जो मधुमक्खियों के माध्यम से भरपूर परागण द्वारा शहद में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक अमृत प्रदान करते हैं।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता के शहद के उत्पादन की क्षमता है जो ग्रामीणों के लिए एक बढ़िया व्यवसाय प्रस्ताव है। "इस पहल को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता' के आह्वान के साथ जोड़ा गया है। मधुमक्खी पालन से न केवल शहद उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि मधुमक्खी के मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, और मधुमक्खी के जहर जैसे अन्य उत्पाद भी विपणन योग्य होंगे और नौकरी के लिए अन्य शहरों की ओर पलायन किए बिना ग्रामीणों को अच्छी आमदनी हो सकती है।"

उन्होंने कहा, "मधुमक्खी कालोनियों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र में समग्र कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।"

इस बीच, केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में 3000 मधुमक्खी के बक्से के वितरण की योजना भी बनाई है। इनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सीतापुर, बुलंदशहर और बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और खगड़िया जैसे जिले शामिल हैं।

• • • •

पाक फायरिंग के बीच, जम्मू-कश्मीर में केवीआईसी हनी मिशन का विस्तार

भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और सीमा पार से गोलीबारी के बावजूद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने जम्मू और कश्मीर में अपने महत्वाकांक्षी हनी मिशन को फिर से शुरू किया है। शुक्रवार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने पाकिस्तान से गोलीबारी के बीच जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में शून्य-रेखा (भारत-पाक सीमा) से लगे ग्रामीणों को 800 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए।

गाँव के 80 प्रशिक्षित किसानों को मधुमक्खी के बक्से दिए गए, जिनमें 15 महिलाएँ लाभार्थी हैं। कठुआ में 800 मधुमक्खी के बक्सों के वितरण ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जम्मू-कश्मीर में केवीआईसी के हनी मिशन को फिर से शुरू करने के लिए चिह्नित किया। इससे पहले, केवीआईसी ने 1 जून को लॉकडाउन हटाए जाने के बाद, 3 जून को अरुणाचल प्रदेश के चुल्लियु गांव में 250 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए।

कठुआ जिला, जो जम्मू और कश्मीर का प्रवेश द्वार है, के स्थान का अपना लाभ है। जिले में उपोष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण तक विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं जो कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मुख्य ताकत है। इसके अलावा, तिलहनी फसलों जैसे सरसों और सूरजमुखी से लेकर मक्का और दलहन की फसलों के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में शहद उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, जिले में खैर, कीकर, नीलगिरी एवं हर्बल और औषधीय वृक्षारोपण की एक विस्तृत श्रृंखला है जो मधुमक्खी पालन का समर्थित वतावरण करती है।

जिन ग्रामीणों को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए,

उन्होंने केवीआईसी को उनके गांव में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया। लाभार्थी अनीता ने कहा कि मधुमक्खी पालन की गतिविधि गाँव में स्वरोजगार को बढ़ावा देगी और दूसरों को भी आजीविका के अच्छे स्रोत के रूप में मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। एक अन्य ग्रामीण, सुरेश ने कहा कि क्षेत्र में उपलब्ध फसलों से अच्छी गुणवत्ता वाले बहु-वनस्पति शहद का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि जिले में उत्पादित अधिकांश शहद स्थानीय रूप से बेचा जाता है और मधुमक्खी पालकों को अच्छी राशि मिलती है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्वरोजगार सृजन और किसानों की आय में वृद्धि करना केंद्र सरकार का प्रमुख फोकस है। श्री सक्सेना ने कहा, "जम्मू और कश्मीर में मधुमक्खी पालन की पहल को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भरता' के आह्वान के साथ जोड़ा गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, जम्मू-कश्मीर में उच्च गुणवत्ता वाले उत्कृष्ट शहद के उत्पादन की असीम क्षमता है, जिसे प्रीमियम मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा, मधुमक्खी के मोम, पराग, प्रोपोलिस, रायल जेली और मधुमक्खी के जहर जैसे उत्पाद भी बाजार में हैं और इसलिए, स्थानीय लोगों के लिए एक लाभदायक प्रस्ताव है।"

बता दें है कि केवीआईसी ने अभी तक जम्मू-कश्मीर में 6500 लोगों को लाभान्वित करने के लिए 6500 मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए हैं। इसमें 2018 में कुपवाड़ा जिले में भारतीय सेना के समर्थन से एक ही दिन में 2330 मधुमक्खी बक्से को वितरित करने का विश्व रिकॉर्ड भी शामिल है, उसी वर्ष असम में काजीरंगा वन क्षेत्र में 1000 मधुमक्खी बक्से को मिंग जनजाति को वितरित करने का अपना ही पिछला रिकॉर्ड है। श्री सक्सेना ने बताया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देशभर में अब तक 1.33 लाख मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्कृष्ट शहद का उत्पादन करते हैं जिसे प्रीमियम मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा, मधुमक्खी के मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी के जहर जैसे उत्पाद भी बाजार में हैं और इसलिए, स्थानीय लोगों के लिए एक लाभदायक प्रस्ताव है।"

केवीआईसी के नीरा एवं ताड़गुड़ उद्योग में नए रोजगार व जैविक उत्पादों के सामने आने की संभावना

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने नीरा एवं ताड़गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना आरंभ की है जिसमें देश में रोजगार सृजन की भारी संभावना है। इस परियोजना का उद्देश्य साफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पाशिकों (ट्रैपर) के लिए स्व-रोजगार का सृजन करना भी है। यह परियोजना मंगलवार को महाराष्ट्र, जहां 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं, के पालघर जिले के दहानु में लांच की गई।

केवीआईसी ने नीरा निकालने एवं ताड़गुड़ बनाने के लिए 200 स्थानीय कारीगरों को टूल किट बांटे जिन्हें केवीआईसी द्वारा 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। 15,000 रुपये के मूल्य के बराबर के इस टूल किट में फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, परफोरेटेड मोल्ड्स, कैंटीन बर्नर्स एवं चाकू, रस्सी तथा नीरा निकालने के लिए कुल्हाड़ी जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं। यह पहल 400 स्थानीय पारंपरिक पाशिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगी।

नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। तथापि, संस्थाकृत बाजार तकनीक के अभाव के कारण, अभी तक नीरा का व्यावसायिक उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर विपणन आरंभ नहीं हुआ है। यह परियोजना केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी की पहल पर शुरू की गई है जो नीरा को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए साफ्ट ड्रिंक के रूप में नीरा का उपयोग करने के लिए राज्य की कुछ बड़ी कंपनियों को शामिल करने की संभाव्यता की भी खोज कर रहे हैं। देश भर में लगभग 10 करोड़ ताड़ पेड़ हैं। इसके अतिरिक्त, अगर समुचित तरीके से मार्केटिंग की जाए तो कैंडी, मिल्क चाकलेट, पाम कोला, आईसक्रीम जैसे उत्पादों की व्यापक श्रृंखला तथा पारंपरिक मिठाइयां भी नीरा से तैयार की जा सकती हैं। वर्तमान में, देश में 500 करोड़ रुपये के बराबर के ताड़ गुड़ नीरा का व्यापार किया जाता है। नीरा के व्यावसायिक उत्पादन के साथ इस टर्नओवर में कई गुना बढोतरी होने की संभावना है।

केवीआईसी ने नीरा तथा ताड़ गुड़ के उत्पादन पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। प्रस्ताव किया गया है कि

नियंत्रित स्थितियों के तहत नीरा का मानकीकृत संग्रह, प्रसंस्करण तथा पैकिंग आरंभ की जाए जिससे कि इसे किण्वन से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य कोल्ड चेन के जरिये प्रसंस्कृत नीरा का बी2सी सप्लाई चेन तक पहुंचना है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कारीगरों को टूल किट वितरित करते हुए कहा ' नारियल पानी की तर्ज पर, हम नीरा को बाजार में उपलब्ध सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने पर कार्य कर रहे हैं। नीरा जैविक है तथा पोषकों में समृद्ध है और इस प्रकार एक संपूर्ण स्वास्थ्य पेय है। नीरा के उत्पादन एवं विपणन में बढोतरी के साथ, हम इसे भारत के ग्रामीण उद्योग के एक प्रमुख कार्यक्षेत्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। '

श्री सक्सेना ने कहा कि नीरा के उत्पादन में बिक्री तथा स्व रोजगार के सृजन के रूप में भारी संभावना है। सक्सेना ने कहा, 'ताड़ उद्योग भारत में रोजगार का एक प्रमुख सृजक हो सकता है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर एवं वोकल फार लोकल की अपील के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ, नीरा में निर्यात की भी असीम संभावनाएं हैं क्योंकि श्रीलंका, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं म्यांमार जैसे देशों में भी इसका उपभोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ताड़ प्रक्षेत्रों की बहुतायत है जो भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी उत्पादक बना सकते हैं।

आयोग ने पोखरण की कुम्हारी प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया

राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से शहर, पोखरण की एक समय सबसे प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला को पुनः प्राप्ति के लिए, जहां पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने आज पोखरण में 80 कुम्हारों के परिवार को 80 इलेक्ट्रिक पॉटर चाकों का वितरण किया, जिनके पास टेराकोटा उत्पादों की समृद्ध विरासत मौजूद है। पोखरण में 300 से ज्यादा कुम्हार परिवार रहते हैं जो कई दशकों से मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुम्हारों ने काम में कठिन परिश्रम और बाजार का समर्थन नहीं मिलने के कारण अन्य रास्तों को तलाश करना शुरू कर दिया था।

इलेक्ट्रिक चाकों के अलावा, केवीआईसी ने 10 कुम्हारों के समूह में 8 अनुमिश्रक मशीनों का भी वितरण किया है, जिनका इस्तेमाल मिट्टी को मिलाने के लिए किया जाता है जो सिर्फ 8 घंटे में 800 किलो मिट्टी को कीचड़ में बदल सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 800 किलो मिट्टी तैयार करने में 5 दिन लगते हैं। केवीआईसी ने गांव में 350 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है। केवीआईसी द्वारा 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए सभी 80 कुम्हार, कुछ उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के साथ आए हैं। इन उत्पादों में कुल्हड़ से लेकर सजावटी वस्तुएं जैसे फूलों के गुलदस्ते, मूर्तियां और दिलचस्प पारंपरिक बर्तन जैसे कि संकीर्ण मुंह वाली गोलाकार बोतलें, लंबी टोंटी वाले लोटस और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य गोलाकार बर्तन शामिल हैं।

कुम्हारों द्वारा शानदार तरीके से "स्वच्छ भारत अभियान"

और "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" को अपनी मिट्टी के बर्तनों की कला के माध्यम से दर्शाया गया है। संयोगवश, यह रविवार के दिन मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ मेल भी खाता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्ट्रिक चाकों और अन्य उपकरणों का वितरण करने के बाद, केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस अभ्यास को प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के आह्वान के साथ जोड़ लिया है और इसका उद्देश्य कुम्हारों को मजबूती प्रदान करना, स्व-रोजगार उत्पन्न करना और मृतप्राय हो रही मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है।

श्री सक्सेना ने कहा कि, "पोखरण को अब तक केवल परमाणु परीक्षणों के स्थल के रूप में जाना जाता था, लेकिन बहुत जल्द ही इसकी पहचान उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के रूप में की जाएगी। कुम्हार सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्यधारा में वापस लेकर आना है। कुम्हारों को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करके, हम उन्हें समाज के साथ जोड़ने और उनकी कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं।"

केवीआईसी अध्यक्ष द्वारा राजस्थान में केवीआईसी के राज्य निदेशक को बाड़मेर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों का विपणन करने और उसकी बिक्री के लिए सुविधा प्रदान करने का निर्देश भी जारी किया गया है, जिससे कुम्हारों को विपणन में सहायता प्रदान की जा सके। "पोखरण, नीति अयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों में से एक है। 400 रेलवे स्टेशनों पर केवल मिट्टी/टेराकोटा के बर्तनों में खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है जिनमें से राजस्थान के दो जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं, दोनों प्रमुख रेलमार्ग पोखरण के सबसे नजदीक हैं। केवीआईसी की राज्य इकाई इन शहरों में पर्यटकों के उच्च स्तर को देखते हुए इन रेलवे स्टेशनों पर अपने मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में सुविधा प्रदान करेगी।"

उल्लेखनीय है कि, केवीआईसी द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के कई दूरदराज इलाकों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम से राजस्थान के कई जिलों जैसे जयपुर, कोटा, झालावाड़ और श्री गंगानगर सहित एक दर्जन से ज्यादा जिलों को लाभ प्राप्त हुआ है।

इस योजना के अंतर्गत, केवीआईसी द्वारा बर्तनों के उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिए ब्लिंगर और पग मिल्स जैसे उपकरणों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले कठिन परिश्रम को भी समाप्त कर दिया है और इसके कारण कुम्हारों की आय 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ गई है।

परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण के उद्देश्य से आयोग ने नई पहल के रूप में चंदन एवं बांस के वृक्षारोपण की शुरुआत की

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपने प्रकार की पहली पहल के रूप में, अपनी परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए चंदन और बांस के वृक्षारोपण की शुरुआत की है, जिनका अभी तक दोहन तक नहीं गया है लेकिन अत्यधिक लाभदायक उद्यम है। चंदन और बांस के व्यावसायिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, केवीआईसी ने 262 एकड़ जमीन में फैले हुए अपने नासिक प्रशिक्षण केंद्र में चंदन और बांस के 500 पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत कर दी है।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने केवीआईसी के पहल की सराहना की है।

केवीआईसी द्वारा चंदन के पौधों की खरीद एमएसएमई मंत्रालय की इकाई, फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर (एफएफडीसी), कन्नौज, उत्तर प्रदेश से और बांस के पौधों की खरीद असम से की गई है। केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वृक्षारोपण समारोह का शुभारंभ किया।

केवीआईसी के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करने के उद्देश्य के साथ, चंदन के वृक्षारोपण की योजना भी बनाई गई है क्योंकि अगले 10 से 15 वर्षों में इसके माध्यम से 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये के बीच आने का अनुमान है। चंदन का एक पेड़ 10 से 15 साल में परिपक्व हो जाता है और वर्तमान दर के अनुसार, 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक बिकता है।

इसी प्रकार, असम से लाई गई अगरबत्ती की लकड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले बांस की एक विशेष किस्म, बम्बुसा तुलदा को महाराष्ट्र में लगाया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय अगरबत्ती उद्योग को समर्थन प्रदान करना और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए नियमित आय उत्पन्न करना है।

एक बांस का पेड़ तीसरे वर्ष में कटाई के योग्य हो जाता है। एक परिपक्व बांस का लट्ठ, जिसका वजन लगभग 25 किलो होता है, औसतन 5 रुपये प्रति किलोग्राम के औसत दर से बिकता है। इस दर पर बांस के एक परिपक्व लट्ठ की कीमत लगभग 125 रुपये होती है। बांस के पौधे में अद्वितीय गुण होता है। प्रत्येक बांस का पौधा, तीसरे वर्ष के बाद, न्यूनतम 5 लट्ठ का उत्पादन करता है और उसके बाद, बांस के लट्ठ का उत्पादन प्रत्येक वर्ष दोगुना हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 500 बांस के पौधों से तीसरे वर्ष में कम से कम 2,500 बांस के लट्ठ प्राप्त होंगे और इससे लगभग

3.25 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी जो प्रत्येक वर्ष दोगुनी रूप से बढ़ेगी।

इसके अलावा, मात्रा के हिसाब से, 2,500 बांस के लठ्ठ का वजन लगभग 65 मीट्रिक टन होगा, जिसका उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाएगा और इस प्रकार से बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार का निर्माण होगा।

पिछले कुछ महीनों में केवीआईसी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में, बम्बुसा तुलदा के लगभग 2,500 पेड़ लगाए हैं। अगरबत्ती निर्माताओं के लिए सही कीमत पर कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नासिक में नवीनतम वृक्षारोपण के अलावा दिल्ली, वाराणसी और कन्नौज जैसे शहरों में बम्बुसा तुलदा के 500 पौधे लगाए गए हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि “खाली जमीन पर चंदन और बांस के पेड़ों को लगा कर परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण का लक्ष्य है। इसी समय, यह चंदन की विशाल वैश्विक मांग को पूरा करके दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा, जबकि बांस का वृक्षारोपण स्थानीय अगरबत्ती निर्माताओं को समर्थन प्रदान करेगा । केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत में अगरबत्ती निर्माण 'आत्मानिर्भर' बनाने के लिए किए गए निर्णय के आलोक में श्री सक्सेना ने कहा कि "हम पूरे देश में केवीआईसी की और ज्यादा परिसंपत्तियों की पहचान कर रहे हैं, जहां पर इस प्रकार के वृक्षारोपण शुरू किए जा सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसानों के द्वारा अपने खेतों में सिर्फ दो चंदन का पेड़ लगाना शुरू कर दिया जाता है, तो वे किसी भी वित्तीय स्थिति का सामना करने के लिए वे आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्म-निर्भर बन जाएंगे।

चंदन के पेड़ों का वृक्षारोपण करने की निर्यात बाजार में भी उच्च क्षमता है। चंदन और इसके तेल की चीन, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भारी मांग है। हालांकि, चंदन की आपूर्ति बहुत कम है और इसलिए भारत के लिए चंदन के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और चंदन के उत्पादन में एक वैश्विक लीडर बनने का एक सुनहरा अवसर है।

आयोग ने वाराणसी के कुम्हार समुदाय के 80 परिवारों को सशक्त बनाया, परिवार "स्वदेशी ओनली" के नए ध्वजवाहक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, वाराणसी में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले समुदाय, आने वाले त्यौहार के मौसम में "स्वदेशी ओनली" उत्पादों के साथ देश में एक नयी मिसाल बनाने के लिए तैयार हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) वाराणसी में "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के हिस्से के रूप में इन समुदायों को मिट्टी के दीयों, देवी / देवताओं की मूर्तियों और मिट्टी के अन्य बर्तनों को बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज चार गाँवों - इटहराडीह, अहरौराडीह, अर्जुनपुर और चक सहजंगीगंज के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले समुदायों से जुड़े 80 परिवारों को बिजली से चलने वाले पहिये (पॉटर व्हील) वितरित किए। इनमें से प्रत्येक गाँव में लगभग 150 से 200 कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो कई पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। हालांकि, हाथ से संचालित किये जाने वाले चाकों की पुरानी तकनीकों, हाथों-औजारों से मिट्टी तैयार करने और विपणन सहायता में कमी के कारण, इन लोगों ने वर्षों से आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना शुरू कर दिया है। केवीआईसी ने अगले 3 महीनों के दौरान वाराणसी में 1500 बिजली से चलने वाले पहियों (पॉटर व्हील) के वितरण का लक्ष्य रखा है।

केवीआईसी ने वाराणसी के सेवापुरी में 300 प्रवासी श्रमिक परिवारों को 300 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स और अन्य उपकरण वितरित करने की योजना तैयार की है। ये प्रवासी श्रमिक कोविड -19 लॉकडाउन के मद्देनजर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और अन्य राज्यों से लौटे हैं। केवीआईसी ने अब तक 60 प्रवासी कामगारों के परिवारों को प्रशिक्षित किया है। अगले महीने 300 परिवारों को पॉटरी टूल किट वितरित किये जायेंगे। इससे केवल वाराणसी में प्रवासियों श्रमिकों के लिए रोज़गार के लगभग

1200 अवसरों के सृजित होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थानीय रोज़गार का निर्माण करना है ताकि उन्हें आजीविका की तलाश में अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता न पड़े।

इस अवसर पर कुम्हार सशक्तिकरण योजना के पुराने लाभार्थियों ने वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से केवीआईसी के अध्यक्ष से बात की। किशन प्रजापति ने कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत केवीआईसी से इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील मिलने के बाद वे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हर दिन लगभग 3000 कुल्हड़ बेचते हैं। इस योजना के एक अन्य लाभार्थी, अक्षय कुमार प्रजापति ने बताया कि वे मिर्जापुर जिले के स्थानीय चूना बाजार में लगभग 4000 कुल्हड़ और प्लेटें बेचने में सक्षम हैं और अब वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर हैं। दयाशंकर प्रजापति ने कहा कि वह वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर दूध के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 3500 मिट्टी के गिलास बेचकर अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने कहा कि वे मिट्टी के बर्तन बेचकर प्रति माह लगभग 20,000 रुपये कमा रहे हैं।

वाराणसी के इन गांवों में ये समुदाय विशेष रूप से दशहरा और दीपावली के आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के मैजिक लैंप, पारंपरिक दीपक (दीया) और लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। त्यौहारों के मौसम में लोगों को चीनी लाइट और अन्य सामान के बजाए स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह भी किया जायेगा।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि वाराणसी को मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के क्षेत्र में बड़ी संभावना के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा "कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत वाराणसी के कई गाँव पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। केवीआईसी वाराणसी में एमएसएमई मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत एक क्लस्टर स्थापित करने जा रहा है। श्री सक्सेना ने कहा कि क्लस्टर लगभग 500 कारीगरों को अच्छी सुविधा वाले स्थान पर काम करने का अवसर प्रदान करेगा।

नीति आयोग द्वारा वाराणसी को आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित किया गया है और केवीआईसी ने सेवापुरी को प्राथमिकता के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों के विकास के लिए चुना है। इसके तहत कारीगरों को प्रशिक्षण देकर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। केवीआईसी ने अब तक देश भर में 17,000 से अधिक इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स वितरित किये हैं। ♦ ♦ ♦ ♦

सीएपीएफ कैंटीन में राष्ट्रीय ध्वज, खादी कुर्ता और जैकेट केवीआईसी की पहली 'स्वदेशी' आपूर्ति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में "स्वदेशी" सामानों की आपूर्ति शुरू कर दी है। आयोग को राष्ट्रीय ध्वज, खादी कुर्ता, सूती जैकेट, शहद और अन्य खाद्य सामग्रियों सहित 13 उत्पादों के लिए दिल्ली में पांच सीएपीएफ कैंटीन से आदेश मिले हैं। आदेश की प्रतिपूर्ति होते ही उत्पादों की आपूर्ति शुरू हो गई।

गृह मंत्रालय द्वारा सीएपीएफ कैंटीन के लिए केवीआईसी के माध्यम से केवल स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए अनिवार्य करने का आदेश जारी करने के बाद यह विकास दो सप्ताह के भीतर आया है। यह आदेश एक जून से लागू होगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त आपूर्ति आदेश में कॉटन तौलिए, अचार, सरसों का तेल, अगरबत्ती, पापड़, डालिया, मुरब्बा और आंवला कैंडी शामिल हैं। आयोग को इन कैंटीनों में आपूर्ति किए जाने वाले 63 नए उत्पादों की सूची जैसे खादी के कपड़े, ऊन, सौंदर्य प्रसाधन जैसे हर्बल तेल, शैम्पू, साबुन, फेस वाश, चाय और कॉफी और अन्य की भी आपूर्ति की गई है।

इस कदम का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण उद्योगों को मज़बूत करना है ताकि भारत को "आत्मानिर्भर" बनाया जा सके, जैसाकि माननीय प्रधान मंत्री ने आह्वान किया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इससे किसानों, बेरोजगार युवाओं और कुटीर और ग्रामोद्योग से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। "हमें 13 उत्पादों की आपूर्ति के लिए अर्धसैनिक कैंटीन से आदेश मिला है और आपूर्ति शुरू हो चुकी है।" श्री सक्सेना ने कहा, आने वाले दिनों में इन कैंटीनों में और अधिक उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे, केवीआईसी इन स्टोरों पर अधिकांश आपूर्ति को पूरा करेगा।

इन आपूर्ति के साथ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग 10 लाख से अधिक अर्धसैनिक कर्मियों के परिवारों से कम से कम 50 लाख लोगों को अपने उपभोक्ता आधार से जोड़ेगा। सद्भावना के संकेत के रूप में, आयोग ने तुरंत ही सीएपीएफ कैंटीनों को 3% के छोटे अंतर पर, जबकि अन्य मामलों में 20% मार्जिन पर, उत्पादों की आपूर्ति करने का फैसला किया है।

विशेष रूप से, देश भर में इन बलों के 20 मास्टर भंडारों (बिक्री केन्द्रों) हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 1800 करोड़ रुपये से अधिक है। सीएपीएफ कैंटीन में स्थानीय उत्पादों की यह आपूर्ति भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादन और बिक्री को प्रभावित करेगी।

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

Social Media Campaigns

Instagram Grid

Special Day posts

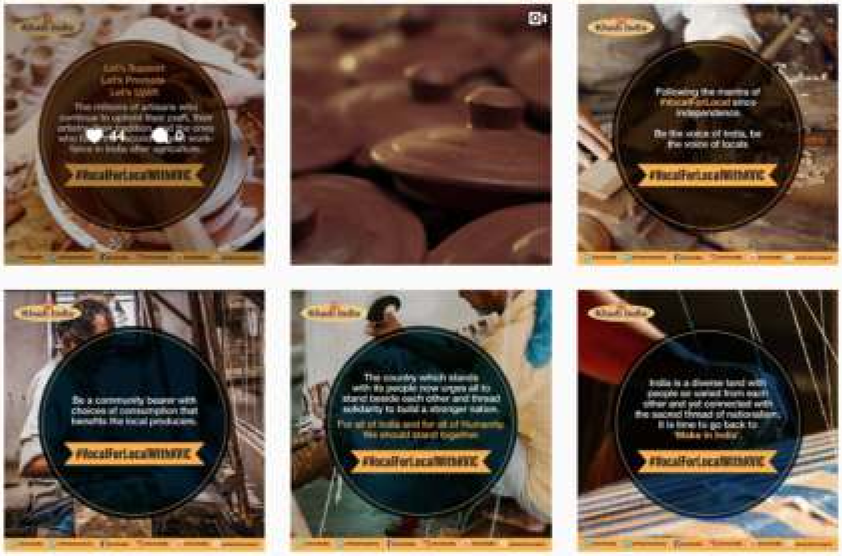

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

Social Media Campaigns

• Posts Series •

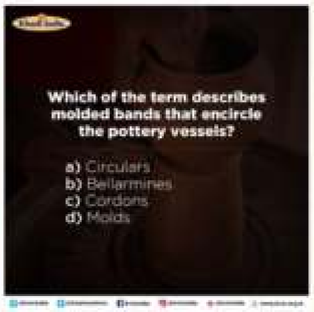

सत्यमेव जयते

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises,
Government of India.

Khadi India

हस्तनिर्मित

स्विट्जरलैंड से पेन और घड़ियाँ,
फ्रांस से चमड़े के जूते,
इटली से पर्स व बटुए और
मिस्र से कॉटन वस्त्र.

आप इन विदेशी वस्तुओं के लिए हजारों खर्च करते हैं और खरीदते हैं,
और जब भारतीय हस्तशिल्प खरीदने की बात आती है, आप संकोच करते हैं !

इस अवसर पर

अपने शहर के किसी खादी इण्डिया आउटलेट पर जाएं,
गर्व से खरीदें उच्च गुणवत्ता के हस्तनिर्मित वस्त्र और उत्पाद,
जो आपके देशवासियों द्वारा ग्रामीण भारत में बनाये गए हैं !

क्यों विदेशी हाथों को भुगतान करें ?
भारत की आत्मीयता को महसूस करें

KVIC ARTWING 2018

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाइट : www.kvic.org.in

https://www.msme.gov.in | Follow us on minmsme @minmsme | Website: www.kvic.org.in | Follow us on kvicindia @kvicindia